



मुख्यमंत्री सचिवालय

प्रेस विज्ञप्ति

राँची, दिनांक-05.07.2019

संख्या-400/2019

05 जुलाई 2019

झारखंड मंत्रालय, राँची

=====

झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा की

=====

★ कार्मिक विभाग ने विभिन्न चयन प्राधिकार के द्वारा पिछले 4 साल में विभिन्न पदों पर 45,176 लोगों की सीधी नियुक्ति करायी

★ कार्मिक ने बताया कि अगले 6 महीनों के भीतर 15,139 नियुक्ति होगी

★ अमीन की नियुक्ति के लिए कैंपस सलेक्शन करें

★ सर्ड में अमीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी

★ अगले 30 दिन में सभी लंबित प्रमाण पत्र निर्गत करें--कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई

-रघुवर दास, मुख्यमंत्री झारखण्ड

=====

कार्मिक विभाग ने विभिन्न चयन प्राधिकार के द्वारा पिछले 4 साल में विभिन्न पदों पर 45,176 लोगों की सीधी नियुक्ति करायी। विभाग आने वाले 6 महीनों के भीतर 15,139 प्रक्रियाधीन नियुक्ति को पूरा करे. मुख्यमंत्री ने प्रक्रियाधीन 3676 रिक्तियों पर 2734 पद सितंबर 2019 तक तथा शेष दिसम्बर तक बहाली पूरा करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया धीमी रही है. यही कारण है कि हर विभाग में मैन पावर की कमी थी. वर्तमान सरकार के गठन के बाद सरकारी नियुक्तियों में भी तेजी आई है. आने वाले 6 महीनों में वैसी विभिन्न विभागों की लगभग 20 हजार सरकारी नियुक्ति जो प्रक्रिया में है उसे पूरा कर लिया जाएगा. उक्त बातें मुख्यमंत्री ने आज झारखंड मंत्रालय में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कार्य प्रगति पर समीक्षा करते हुए कहीं.

आदिम जनजाति के लिए कट ऑफ मार्क्स 30 प्रतिशत

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि आदिम जनजाति समाज के युवक-युवतियों को सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में राज्य सरकार द्वारा कट ऑफ मार्क्स में छूट दिया जा रहा है. इन्हें अब विभिन्न चयन प्राधिकार द्वारा लिए जाने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स 30% रखे जाने का निर्णय लिया गया है.

शिक्षक बहाली में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ मार्क्स 45% से घटाकर 40% तथा आदिम जनजाति के लिए 38% अंक

मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान यह बात आयी कि कई अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में लंबे समय तक पिछड़े होने के कारण वर्तमान कटऑफ के आधार पर उक्त संवर्ग में शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं तथा पद रिक्त रह जा रहे हैं। विषय पर संपूर्णता से विचार कर यह निर्णय लिया कि शिक्षक बहाली में अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स 45% से घटाकर 40% की जाय तथा आदिम जनजाति के लिए कट ऑफ मार्क्स 38% अंक की जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद से ही आदिम जनजाति , अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को उच्च शिक्षा के प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य नहीं हुए थे. वर्तमान सरकार ने इन समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए लोगों को कई विभिन्न योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया है. इन समुदायों के भी युवक युवतियां पढ़ें और आगे बढ़े इसके लिए सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है.

स्थानीय नीति का मिला है फायदा

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य में स्थानीय नीति लागू की है. सभी प्रकार की नियुक्तियों में स्थानीय नीति के लागू होने से राज्य के युवाओं को पूरा फायदा मिला है. राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल सरकारी नियुक्तियों का 95% नौकरी स्थानीय लोगों को ही मिला है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी सरकार ने स्थानीय नीति को लागू करने का काम नहीं किया था इसी वजह से राज्य के सरकारी नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहती थी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने स्पष्ट नीति और साफ नियत के साथ सभी बहालियों पर पूरी पारदर्शिता रखी है.

मुख्यमंत्री ने छात्र हित में लिया बड़ा फैसला

लिपिक के पदों के लिए 25 शब्द प्रति मिनट तथा 2% से अधिक गलती न होने के स्थान पर 5% से अधिक गलती न होने को जोड़ने का फैसला

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि लिपिक के पदों के लिए 25 शब्द प्रति मिनट तथा 2% से अधिक गलती न होने के स्थान पर 5% से अधिक गलती न होने को जोड़ने का फैसला लिया गया. आशुलिपिक के पदों के लिए 0% के बदले 2% से अधिक गलती न होने का फैसला लिया गया. जो लोग क्वालीफाई करेंगे उन्हें अनिवार्य टाइपिंग प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जाएगा.

अमीन की नियुक्ति के लिए कैंपस सलेक्शन करने का निर्देश

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में अमानत (अमीन) की बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं. अमीन की रिक्तियों को भरने के लिए रांची विश्वविद्यालय में चल रहे अमीन के पाठ्यक्रम पर उत्तीर्ण छात्रों का कैंपस सलेक्शन करें. रांची विश्वविद्यालय से जो भी बच्चे अमानत की पढ़ाई किए हैं उन्हें कैंपस सेलेक्शन के जरिए सीधी नियुक्ति दें. "हृनरमन्द बनो और नौकरी पाओ"

साथ ही, सर्द में अमीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य में अमीन की भारी कमी को देखते हुए राज्य सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ समन्वय बनाकर रांची के सर्द में अमानत (अमीन) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत करे.

प्रमाण पत्र निर्गत करने में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने अपर मुख्य सचिव सह कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सचिव श्री केके खंडेलवाल को निदेश दिया कि राज्य के सभी प्रखंडों के सर्कल ऑफिसर तथा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को

एक चिट्ठी निर्गत करें जिसमें यह साफ निर्देश रहे कि प्रमाण पत्र से जुड़े जो भी आवेदन लम्बित हैं उसे अगले 30 दिनों के अंदर पूरा कर लें. मुख्यमंत्री ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र , आवासीय प्रमाण पत्र , आय प्रमाण पत्र इत्यादि निर्गत करने संबंधी शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आम जनता को सरल एवं सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराना प्राथमिकता रही है. अधिकारी गरीब आम जनता को बेवजह कार्यालय का चक्कर नहीं लगवाएं. कोई भी सीओ या बीडीओ अनावश्यक रूप से प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अगर प्रमाण पत्र निर्गत करने में किसी प्रकार का कोताही करें तो आम जनता 181 में शिकायत दर्ज कराएंगे. काम लटकाने वाले अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.

ग्राम सभा एवं वार्ड समिति की अनुशंसा से भी निर्गत होंगे जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहा कि जिन लोगों का नाम खतियान में नहीं है उन्हें जाति प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्रखंड कार्यालय दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे ग्राम सभा की अनुशंसा या मुखिया के अनुशंसा के आधार पर जाति प्रमाण पत्र तथा आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जा सकेगा. शहरी क्षेत्रों में वार्ड समिति की अनुशंसा पर प्रमाण पत्र निर्गत करने में सक्षम होंगे. इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बैठक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.

बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव श्री केके खंडेलवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री एपी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव जेपीएससी श्री रणेंद्र कुमार, उप सचिव जेएसएससी श्री राजू रंजन, संयुक्त सचिव कार्मिक श्री एके खेतान, संयुक्त सचिव श्री एके सत्यजीत, संयुक्त सचिव श्री ओम प्रकाश शाह, संयुक्त सचिव श्री सतीश कुमार जायसवाल एवं उप सचिव श्री चंद्रभूषण प्रसाद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

###

=====

#TeamPRD(CMO)